जी20 अर्थव्यवस्था में भारत सबसे आगे

ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं ने आर्थिक सुधारों दीर्घकालिक नीतियों की सराहना की

नई दिल्ली 9 जुलाई ,आर्थिक सुधारों, निवेश-अनुकूल नीतियों और तेज़ विकास दर के दम पर भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योगपतियों और कॉरपोरेट नेताओं ने भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा है कि देश पिछले पांच वर्षों से लगभग आठ प्रतिशत की औसत विकास दर के साथ जी20 देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है.

उनका मानना है कि संरचनात्मक सुधारों, तकनीकी प्रगति और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बना दिया है.

एएनजेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुनो माटोस ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए हैं, जिनका सकारात्मक असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. उनके अनुसार, देश तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हुआ है. उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत की विकास दर करीब आठ प्रतिशत रही है, जो जी20 देशों में सबसे अधिक है.

> ऑस्ट्रेलियन सुपर के सीईओ पॉल श्रोडर ने कहा कि भारत में दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण और निवेश समर्थक नीतियों ने विदेशी निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई अपनी पूर्व बैठकों में उन्हें यह महसूस हुआ कि सरकार व्यापार और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझती है. उनके अनुसार, स्थिर नीतिगत माहौल और भविष्य की स्पष्ट आर्थिक रणनीति निवेशकों को भरोसा देती है, जिससे भारत में पूंजी निवेश की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं.

चार दिन में चांदी 15,000 टूटी सोना भी फिसला

नई दिल्ली 9 जुलाई. वैश्विक अनिश्चितताओं और निवेशकों की सतर्कता के बीच घरेलू वायदा बाजार में सोना और चांदी लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी 2,000 रुपये यानी लगभग एक प्रतिशत टूटकर 2,21,502 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. पिछले चार कारोबारी दिनों में चांदी की कीमत में करीब 15,000 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है. वहीं अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना 610 रुपये टूटकर 1,43,101 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और महंगाई व ब्याज दरों को लेकर बढ़ी चिंताओं का असर कीमती धातुओं के बाजार पर देखने को मिला.

आईटी गिरावट ने बढ़ाया बड़ा निवेश

भारी बिकवाली के बीच अधिकांश निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं

मजबूत कैश फ्लो और स्थिर बिजनेस लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न

मुंबई 9 जुलाई, आईटी सेक्टर में पिछले छह महीनों से जारी भारी बिकवाली के बीच जहां अधिकांश निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं, वहीं देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम, पराग पारिख फ्लेक्सीकैप फंड, ने उल्टा दांव खेलते हुए प्रमुख आईटी कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाया है.

लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले इस फंड ने जून महीने में टीसीएस, इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अतिरिक्त शेयर खरीदे हैं. यह खरीदारी ऐसे समय में हुई है जब तीनों कंपनियों के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 40 से 55 प्रतिशत तक नीचे कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी आईटी इंडेक्स भी पिछले छह महीनों में 25 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है. फंड के मासिक पोर्टफोलियो के अनुसार, जून में इंफोसिस के 54 लाख अतिरिक्त शेयर खरीदकर कुल हिस्सेदारी 4.27 करोड़ शेयर कर दी गई.

> हालांकि, पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड के मुख्य निवेश अधिकारी एवं निदेशक राजीव ठक्कर का मानना है कि निवेश का आधार अल्पकालिक बाजार धारणा नहीं, बल्कि कंपनियों की मजबूत नकदी प्रवाह क्षमता है. उनके अनुसार, भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी डॉलर में राजस्व अर्जित करती हैं, जबकि उनके अधिकांश परिचालन खर्च रुपये में होते हैं. यदि वेतन वृद्धि नियंत्रित रहती है तो इन कंपनियों के मार्जिन और लाभप्रदता में सुधार की संभावना है.

विज्ञापनों के भ्रामक दावों पर एफएसएसएआई सख्त

नई दिल्ली 9 जुलाई, देश में खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और विज्ञापनों में किए जा रहे दावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है. नियामक संस्था ने लोट्टे इंडिया, फर्न्स एन पेटल्स और कुबेरा फूड्स सहित कई कंपनियों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है.

एफएसएसएआई का आरोप है कि कुछ उत्पादों पर '100 प्रतिशत प्राकृतिक', '100 प्रतिशत शाकाहारी' और 'प्रीमियम चॉकलेट' जैसे दावे किए गए, जबकि उत्पादों की वास्तविक सामग्री और लेबलिंग इन दावों के अनुरूप नहीं पाई गई. संस्था ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एफएसएसएआई के अनुसार, जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं. लोट्टे इंडिया के कुछ उत्पादों पर पुराने प्रिंटेड लेबल का उपयोग बिना अनुमति के किया गया. 'लोट्टे चॉको पाय' पर '100 प्रतिशत शाकाहारी' का दावा भ्रामक पाया गया.

पहली छमाही में एनसीआर में मकानों की बिक्री सात फीसदी घटी

नयी दिल्ली, 09 जुलाई देश के आठ प्रमुख आवासीय बाजारों में इस साल की पहली छमाही में घरों की बिक्री में एक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी.नाइट फ्रैंक ने मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता के आंकड़ों के आधार पर गुरुवार को जारी इंडिया रियल एस्टेट रिपोर्ट में बताया कि जनवरी-जून 2026 के दौरान इन आठ शहरों में 1,71,471 आवासीय इकाइयों की बिक्री दर्ज की गयी जो पिछले साल की पहली छमाही में बिके 1,70,201 घरों की तुलना में एक प्रतिशत अधिक है. साथ ही यह पिछले 12 साल की सबसे मजबूत अर्धवार्षिक बिक्री में से एक है.

वैकल्पिक ईंधन वाहनों को परमिट राहत

कमर्शियल वाहनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान

यह सुविधा निजी वाहनों पर लागू नहीं होगी

नई दिल्ली 9 जुलाई, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू परमिट छूट की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है.

साथ ही पहली बार एथेनॉल, मेथेनॉल और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधनों से संचालित कमर्शियल वाहनों को भी इस सुविधा के दायरे में शामिल किया गया है. इस फैसले का उद्देश्य कम

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बढ़ावा देना, परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाना और ऑपरेटरों के लिए नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना है.

देश में टैक्सी, बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों को विभिन्न राज्यों में संचालन के लिए नेशनल परमिट या ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जैसी अनुमतियों की आवश्यकता होती है. इन परमिटों के लिए आवेदन, दस्तावेजों की जांच और निर्धारित शुल्क जैसी कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं. नई व्यवस्था के तहत पात्र इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों को इन प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी.

> सरकार का मानना है कि यदि पर्यावरण अनुकूल वाहनों के लिए नियमों को सरल बनाया जाए तो इनके उपयोग में तेजी आएगी. परिवहन क्षेत्र देश के कुल कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है. ऐसे में इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, मेथेनॉल और हाइड्रोजन आधारित वाहनों को प्रोत्साहन देने से प्रदूषण कम करने के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भी घटाई जा सकेगी. यह कदम ग्रीन मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

निसान ने दुनिया के लिए पेश की भारत में बनी नयी टेकटॉन

नयी दिल्ली, 09 जुलाई जापानी कार निर्माता कंपनी निसान मोटर की भारतीय इकाई निसान मोटर इंडिया ने गुरुवार को भारत में आयोजित विश्व प्रीमियर के दौरान नयी निसान टेकटॉन बाजार में पेश की.

इस साल भारत में पेश किया गया यह निसान का दूसरा नया मॉडल है. यह दो इंजन विकल्पों टर्बो टी160 औ टर्बो टी280 में उपलब्ध है. टी160 की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये और टी280 की शुरुआती कीमत 14.99 लाख रुपये रखी गयी है. कंपनी के अनुसार, यह अपने सेगमेंट की पहली एसयूवी है जिसमें पूरी रेंज में केवल टर्बोचार्ज्ड इंजन दिये गये हैं.

टेकटॉन का निर्माण चेन्नई स्थित निसान प्लांट में किया जायेगा. इसे 'एक कार, एक दुनिया' रणनीति के तहत विकसित किया गया है और भारत के अलावा मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी निर्यात किया जायेगा.

निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक सौरभ वत्स ने कहा कि टेकटॉन भारतीय ग्राहकों को प्रीमियम डिजाइन, अत्याधुनिक तकनीक, शानदार प्रदर्शन और रोजमर्रा की उपयोगिता प्रदान करेगी.

इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म

नई दिल्ली 9 जुलाई, देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई अहम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी समाप्त करने का फैसला किया है. इस निर्णय के तहत डिस्प्ले मॉड्यूल और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले चुनिंदा आयातित पुर्जों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है.

सरकार का मानना है कि इससे घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत कम होगी, स्थानीय स्तर पर वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में गति मिलेगी. यह राहत 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, जिससे कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश और उत्पादन योजनाएं बनाने में सुविधा होगी.

नई व्यवस्था के तहत डिस्प्ले सेल्स, बैकलाइट यूनिट्स, फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंबली एनएफसी कॉइल्स और नियोडिमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है.

साउथ इंडियन बैंक को मिला नया सीईओ

नई दिल्ली 9 जुलाई, निजी क्षेत्र के ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक को नया नेतृत्व मिलने का रास्ता साफ हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महेश मुरलीधर पाई की बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.

यह नियुक्ति 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल तीन वर्षों का रहेगा. बैंक ने नियामकीय फाइलिंग के माध्यम से इस मंजूरी की जानकारी दी है. अब इस प्रस्ताव को 16 जुलाई को होने वाली बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा, जिसके बाद इसे शेयरधारकों की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा.

बैंक के अनुसार, आरबीआई ने 7 जुलाई 2026 को जारी अपने पत्र में महेश मुरलीधर पाई की नियुक्ति को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है. नियामकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह बैंक की कमान संभालेंगे.

फ्लिपकार्ट की फूड कैटेगरी में 50% की भारी बढ़ोतरी

नवभारत, जबलपुर। भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट की फूड एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में सालाना आधार पर 50 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।इस विकास में फ्लिपकार्ट मिनट्स की 25 प्रतिशत भागीदारी के साथ क्विक कॉमर्स सबसे प्रमुख माध्यम बना हुआ है।इस मांग को सबसे ज्यादा तेजी ऐसे युवा और नॉन-मेट्रो ग्राहक दे रहे हैं, जो रेसिपी देखकर, क्रिएटर्स की रिकमेंडेशन पर या वेलनेस ट्रेंड्स के आधार पर मॉडर्न न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स खोज रहे हैं।इस मौके पर फ्लिपकार्ट के वाइस प्रेसिडेंट निशांत दलाल ने कहा कि भारत में खाना अब सिर्फ दिनचर्या नहीं, बल्कि वेलनेस और डिस्कवरी का मामला बनता जा रहा है।

युवाओं और छोटे शहरों में बढ़ा क्रेज

इस सालाना वृद्धि में अकेले 60 प्रतिशत की हिस्सेदारी जेन-ज़ी ग्राहकों की है, जो प्रोटीन ओट्स, पीनट बटर और प्रोटीन मुसली जैसे प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं।इसके साथ ही धुलिया, इंफाल, धारवाड़, उज्जैन, हुबली, मीरगंज और लहरपुर जैसे टियर 2+ बाजारों के उपभोक्ता भी अब कोल्ड-प्रेस्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स जैसे स्वस्थ विकल्पों को तेजी से अपना रहे हैं, जिससे इन प्रोडक्ट्स की सर्च 80 प्रतिशत तक बढ़ गई है।इस बदलते ट्रेंड की झलक फ्लिपकार्ट फूड फेस्ट के तीसरे संस्करण में भी दिखी, जिसमें फराह खान, कुणाल कपूर और रणवीर ब्रार जैसी हस्तियों सहित 50 से ज्यादा ब्रांड्स और 1000 से ज्यादा क्रिएटर्स शामिल हुए, जहाँ हैप्पिलो, फेररो रोशर, वंडरलैंड, केलॉग्स, लुविट, एल्पिनो, मॉन्डलेज, डाबर, फॉर्च्यून और माय फिटनेस जैसे ब्रांड्स ने 10 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस लॉन्च किए।

समाचार विशेष

अलग ही पॉलिटिक्स खेल रहे थलपति विजय

नई दिल्ली. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय को अगर आप सियासत के कच्चे खिलाड़ी समझ रहे हैं तो यह आपकी भूल है. वह अन्य विपक्षी दलों की राह पर न चलकर एकदम नई तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं.

हर नफा-नुकसान का हिसाब लगाकर फूंक-फूंककर कदम रख रहे हैं. थलपति न ज्यादा दोस्ती न ज्यादा बैर के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं. जी हां थलपति विजय अन्य विपक्षी दलों की राजनीति से बिल्कुल अलग तरह की सियासत खेल रहे हैं. उनकी राजनीति में बीजेपी का विरोध जरूर देखा जा रहा है लेकिन पीएम मोदी और केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी देखा जा रहा है.

थलपति विजय ने राजनीति में जैसे ही कदम रखा, तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर दी. 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बार-बार क्ष्छ्क्कपर सत्ता को केंद्रित करने, हिंदी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति थोपने और तमिलनाडु के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेने से बचते नजर आए. थलपति विजय ने वैचारिक और नीतिगत मुद्दों पर बीजेपी का विरोध जारी रखते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के साथ तालमेल लगातार बढ़ाए रखा है. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को प्रशासनिक रिश्तों पर हावी होने देने के बजाय, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने राजनीति में कट्टरता से किनारा किया है. उन्होंने अपने कामकाज से अलग रखने की कोशिश की है. एक ऐसा संतुलन जो हाल के केंद्र-राज्य संबंधों में शायद ही कभी देखने को मिला हो. यह तरीका विपक्ष की राजनीति के लिए एक नया मॉडल बन सकता है. जहां जरूरी हो वहां ही विरोध करें और जहां फायदा हो वहां एकदम सहयोग वाली राजनीति अपनाएं.

> **थलपति विजय की राजनीति अलग कैसे**
>
> उनकी सरकार ने भाजपा के प्रति अपने वैचारिक विरोध को कमजोर नहीं किया है. वह तीन-भाषा नीति को अस्वीकार करती है, शिक्षा निधि को नई नीति से जोड़ने का विरोध करती है, और संघवाद और राज्य स्वायत्तता पर तमिलनाडु के पारंपरिक रुख को बरकरार रखती है. जो बदला है, वह मोदी सरकार के साथ संवाद का तरीका है. विजय ने नई दिल्ली के साथ बातचीत कम करने के बजाय उसे बढ़ाने का विकल्प चुना है.

फेरबदल क्या अब सत्र के बाद!

नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार में फेरबदल का मामला बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गई है. पक ही नहीं रही है. पिछले एक साल से ज्यादा समय से मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा चल रही है. पिछले साल जून में सरकार के एक साल पूरे होने पर बदलाव की चर्चा शुरू हुई थी और इस साल जून बीतने के बाद भी चर्चा जारी है.

अब कहा जा रहा है कि संसद के मानसून सत्र के बाद सरकार में फेरबदल होगी. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मई में मंत्रिपरिषद की बैठक की थी. उसके बाद जून में सचिवों के साथ बैठक की. एनडीए की तीसरी

सरकार के दो साल और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 12 साल का जश्न मनाया गया. अब अक्टूबर में उनके सत्ता में आने के 25 साल पूरे होंगे तो उसकी रजत जयंती का जश्न पूरे देश में मनाया जाएगा. गौरतलब है कि वे अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे. सो, सारे जश्न होंगे और ऐसे हर मौके से पहले चर्चा होगी कि इसके बाद मंत्रिमंडल बदला जाएगा. इन चर्चाओं में दिन, महीने, साल गुजरते जा रहे हैं.

असल में प्रधानमंत्री मोदी छह से 11 जुलाई तक तीन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं. वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे. चार दशक के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जा रहा है.

> **मोदी संसद सत्र तक पुराने मंत्रियों को रखना चाहते हैं**
>
> जानकार सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि संसद के मानसून सत्र में वे नए मंत्रियों को विपक्ष के सामने उतारें. ध्यान रहे मानसून सत्र में सरकार कई ऐसे विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिनको लेकर विवाद चल रहा है. संविधान के 130वें और 131वें संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं. इसके अलावा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने और परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार बैकफुट पर है.

विशेष | **बहुत जल्दी राष्ट्रीय संगठन में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी**

भाजपा संगठन में टल रहा है बदलाव

नई दिल्ली. नितिन नबीन को भाजपा का अध्यक्ष बने छह महीने हो गए. वैसे तो उनको पिछले साल दिसंबर में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. लेकिन जनवरी में वे पूर्णकालिक अध्यक्ष बन गए. तभी से इस बात की चर्चा चल रही है कि बहुत जल्दी राष्ट्रीय संगठन में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी. लेकिन छह महीने में नितिन नबीन नई टीम नहीं बना पाए हैं.

हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे लेकर कुछ नहीं हो रहा है. पिछले कुछ दिनों से तो लगातार बैठकें हो रही हैं. अभी हाल ही में नितिन नबीन, अमित शाह और बीएल संतोष की बैठक हुई है. इससे पहले एक बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हुई थी. उसके बाद नितिन नबीन ने अकेले अमित शाह से मुलाकात की

थी. ऐसी हर मुलाकात के बाद कहा गया कि बहुत जल्दी संगठन में फेरबदल होने जा रही है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा संगठन और केंद्र की सरकार दोनों में बदलाव का मामला आपस में मिल गया है और दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा है.

अब सवाल है कि अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल संसद के मानसून सत्र के बाद होती है तो क्या संगठन में बदलाव उससे पहले हो सकता है? भाजपा के जानकार नेताओं का कहना है कि दोनों को जोड़ने की जरुरत नहीं है. यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने पिछले 12 साल में बदलाव के साथ निरंतरता का सिद्धांत बनाया था. अमित शाह ने जो टीम बनाई थी वह टीम जेपी नड्डा के साथ काम करती थी और धीरे धीरे उसमें से लोग हटे. उसी तरह नड्डा की टीम अभी काम कर रही है और धीरे धीरे लोगों को हटाया जाएगा. चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष 46 साल के हैं इसलिए उनसे बहुत ज्यादा उम्र और अनुभव वाले लोगों को उनकी टीम में नहीं रखा जाएगा. इसलिए सरकार से लाकर संगठन में लोगों को रखने की संभावना कम है. मौजूदा टीम में से कुछ महामंत्रियों की विदाई होगी.

तेलंगाना में पीआरसी पर सियासत तेज

हैदराबाद. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएम आईएम) के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को तेलंगाना सरकार से गरीबों को तत्काल स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि कई गरीबों के पास दस्तावेज नहीं हैं और चल रहे विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से बाहर होने का खतरा है.

हैदराबाद के सांसद ने सवाल उठाया कि आखिर राज्य सरकार पीआरसी जारी करने में क्यों देरी कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर सत्ताधारी दल को यह एहसास नहीं है कि तेलंगाना के गरीबों के पास दस्तावेज नहीं हैं, तो वह वास्तविकता से पूरी तरह कटी हुई है.

ओवैसी ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से कहा कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद लोगों को 'सांत्वना' देने के लिए उनके पास न आएं और फिर साजिश का आरोप न लगाएं. उन्होंने कहा कि अगर कोई साजिश है, तो उन्हें उसका समाधान ढूंढना चाहिए, और समाधान पीआरसी है. सांसद ने बताया कि कर्नाटक सरकार पीआरसी जारी कर रही है और पूछा कि जब कर्नाटक में भी कांग्रेस सत्ता में है, तो तेलंगाना में पीआरसी क्यों नहीं जारी की जा रही है. ओवैसी ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा पहले ही उपमुख्यमंत्री मल्लु भट्टी विक्रमार्क के समक्ष उठाया था. उन्होंने यह भी बताया कि वे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मिलने का समय मांग रहे हैं और कहा कि मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त हैं.

> **सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला**
>
> सांसद ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में जन्मे और जिनके नाम, या उनके माता-पिता और दादा-दादी के नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें पीआरसी (पर्सनल सर्टिफिकेट) जारी की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राज्य के शिक्षण संस्थानों में लगातार चार वर्षों तक अध्ययन करता है, तो वह राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए पात्र हो जाता है. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार पीआरसी जारी करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल रिकॉर्ड और राजस्व रिकॉर्ड को आधार बनाए.